



2026:AHC:177154

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7237 वर्ष

2026

डॉ. वैभव

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गोपाल मिश्रा, शिव मंगल सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आज दाखिल किया गया अनुपालन शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री रवींद्र कुमार सिंह के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया।
3. यह आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 121/2026 में अग्रिम जमानत की मांग के लिए दायर की गई है जो कि मानव अंग और उत्तक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 की धारा 18, 19, 20 और बीएनएस की धारा 111(2), 143(2), 239(ख), 318(4), 319(2), 3(5) के तहत थाना रावतपुर, जिला कानपुर नगर में दर्ज है।
4. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि 31.03.2026 को आवेदक और कई अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 143, 3(5) और मानव अंग और उत्तक प्रतिरोपण अधिनियम,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



1994 (जिसे आगे “1994 का अधिनियम” कहा जाएगा) की धारा 18, 19, 20 के तहत थाना रावतपुर, ज़िला कानपुर नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 121/2026 के रूप में दर्ज किया गया। प्राथमिकी में आरोप है कि आवेदक और प्राथमिकी में नामजद अन्य आरोपी अवैध किडनी प्रतिरोपण में शामिल थे, जो बाहर से आए चिकित्सकों की मदद से आहूजा अस्पताल में किया जा रहा था। प्राथमिकी प्रथम सूचनाकर्ता/सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार द्वारा दर्ज कराई गई थी और अस्पताल के मालिकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

5. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक एक पंजीकृत दन्त चिकित्सक है और मेरठ जिले में दन्त चिकित्सालय चलाता है; वह 2009 से व्यवसाय कर रहा है और उसका पंजीकरण संख्या 6050यूपीडीसीआई है; उसे किडनी प्रतिरोपण की कोई जानकारी या विशेषज्ञता नहीं है। 1994 के अधिनियम के अनुसार, आरोपी आवेदक पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। 1994 के अधिनियम की धारा 22 के तहत पुलिस आख्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। सक्षम अधिकारी की शिकायत के बिना, प्राथमिकी दर्ज करना ही अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसलिए, इसके बाद की सभी कार्रवाई भी अवैध हैं और उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। आवेदक का उस अस्पताल से कोई संबंध नहीं है जहाँ मानव अंग प्रतिरोपण का अवैध काम किया जा रहा था। आवेदक को इस प्रकरण में अन्य सह-आरोपियों, डॉ. सुरजीत आहूजा और डॉ. प्रीति आहूजा के संस्वीकृति कथन के आधार पर आरोपी बनाया गया है। आवेदक के खिलाफ कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है। आवेदक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण मुकदमा चलाया गया है। आवेदक न तो किसी संगठित अपराध का सदस्य है और न ही मानव तस्करी में शामिल है। सह-आरोपी मो. अफजल की गिरफ्तारी पर इस न्यायालय की खंड पीठ ने 18.06.2026 के आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 12032 of 2026 में पारित के तहत रोक लगा दी है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि विवेचनाधिकारी ने आरोपी के खिलाफ काफी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। किडनीदाता आयुष चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि आरोपी इस अपराध में शामिल था। किडनीदाता आयुष चौधरी के बयान के अनुसार, आरोपी ने अपराध में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और 18.03.2026 को आरोपी और सह-आरोपी डॉ. अमित, डॉ. अफज़ल और अन्य लोग उसे गाज़ियाबाद ले गए थे; उसने साफ तौर पर कहा कि शल्यक्रिया के समय आरोपी और अन्य चिकित्सक अस्पताल में मौजूद थे और शल्यक्रिया के बाद उसे दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया था। विवेचनाधिकारी ने आरोपी का कॉल विवरण अभिलेख इकट्ठा किया, जिससे पता चलता है कि किडनीदाता आयुष चौधरी के शल्यक्रिया की तारीख को आरोपी कानपुर ज़िले में मौजूद था। विवेचनाधिकारी ने होटल की आगंतुक पंजिका भी इकट्ठा किया और उसकी एक प्रतिलिपि अनुपालन शपथ-पत्र के साथ जमा की गई है, जिससे पता चलता है कि शल्यक्रिया की तारीख के आस-पास आरोपी अन्य सह-आरोपियों के साथ होटल में ठहरा था। अन्य साक्षियों और सह-आरोपियों ने भी कहा कि आरोपी मानव अंगों के अवैध प्रतिरोपण में शामिल था। उन्होंने आगे कहा कि डॉ. सुरजीत आहूजा और डॉ. प्रीति आहूजा, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार किया था, लगभग चार महीने तक जेल में रहे और उसके बाद ही उनकी जमानत आवेदन स्वीकृत हुई। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए इस प्रकरण में आरोपी से हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है। अगर आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो इससे विवेचना में बाधा आएगी।

7. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने और अभिलेख देखा।

8. आवेदक का नाम प्राथमिकी में है। किडनीदाता आयुष चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि चिकित्सीय परीक्षण करवाने के लिए आवेदक उसे दूसरे अस्पताल ले गया था। दूसरे सह-आरोपी ने भी कहा कि आवेदक शल्यक्रिया करने वाली मंडली का सदस्य था। अभी संज्ञान लेने का चरण नहीं आया है, इसलिए इस चरण पर 1994 के अधिनियम की धारा 22 लागू नहीं होती है। विवेचनाधिकारी ने दोषी लोगों के खिलाफ मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम अधिकारी को सूचित किया है। विवेचनाधिकारी ने शल्यक्रिया की तारीख को कानपुर जिले में आवेदक की मौजूदगी के बारे में उसके खिलाफ काफी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। आवेदक चिकित्सकों की शल्यक्रिया मंडली के सदस्यों में से एक था। प्रथम दृष्टया, आवेदक कथित अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था। वह विवेचना में सहयोग नहीं कर



रहा है और पिछले साढ़े चार महीनों से विधि की पकड़ से बच रहा है। आवेदक को गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से न्याय में बाधा आ सकती है। यह इस न्यायालय की असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त प्रकरण नहीं है।

9. श्रीकांत उपाध्याय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2024) 12 एससीसी 382 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम ज़मानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। इस शक्ति का इस्तेमाल करते समय, न्यायालय को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि गंभीर मामलों में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा या सुरक्षा देने से न्याय में बाधा आ सकती है। जब गिरफ्तारी का वारंट या उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदक असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होता है। संबंधित प्रस्तर संख्या 30 श्रीकांत उपाध्याय (ऊपर) प्रकरण का प्रस्तर 30 इस प्रकार है:

"30. हमने पहले ही माना है कि अग्रिम ज़मानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। हालाँकि कई मामलों में यह माना गया है कि ज़मानत मिलना एक नियम है, लेकिन किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम ज़मानत भी एक नियम है। यह नियम नहीं हो सकता और इसे स्वीकार करने का फैसला हर प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय के सावधानीपूर्वक और समझदारी भरे विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस शक्ति का इस्तेमाल करते समय, संबंधित न्यायालय को बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि गंभीर मामलों में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा या सुरक्षा देने से न्याय में बाधा आ सकती है और विवेचना पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि कभी-कभी इससे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने की कोशिश हो सकती है। हमारा यह मतलब नहीं है कि न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार के दौरान अंतरिम सुरक्षा का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि यह धारा किसी व्यक्ति की आज़ादी को बिना वजह गिरफ्तारी से बचाने के लिए है और हम कहते हैं कि ऐसे आदेश बहुत ज़रूरी मामलों में ही दिए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में, जब गिरफ्तारी का वारंट या उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदक इस असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होता। निश्चित रूप से, इससे न्याय के हित में बहुत ही खास या असाधारण मामलों में अग्रिम ज़मानत देने की न्यायालय की शक्ति पर कोई रोक नहीं लगेगी। लेकिन, जो व्यक्ति लगातार



आदेशों की अवहेलना करता है और फ़रार रहता है, वह ऐसी राहत पाने का हकदार नहीं है।"

10. पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2019) 9 एससीसी 24 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसका मकसद न केवल आरोपी की मौजूदगी सुनिश्चित करना है, बल्कि कई अन्य उद्देश्य भी पूरे करना है। दं.प्र.सं. की धारा 438/बीएनएसएस की धारा 482 के तहत शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर और कम ही किया जाना चाहिए। अग्रिम ज़मानत की सुविधा केवल असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए। पी. चिदंबरम (ऊपर) प्रकरण में संबंधित प्रस्तर संख्या 69 इस प्रकार है:

"69. आम तौर पर, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है, जिसका मकसद न सिर्फ़ आरोपी की मौजूदगी सुनिश्चित करना होता है, बल्कि कई अन्य उद्देश्य भी होते हैं। दं.प्र.सं. की धारा 438 के तहत मिली शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर और कम ही किया जाना चाहिए। अग्रिम ज़मानत की सुविधा केवल खास मामलों में ही दी जानी चाहिए। न्यायालय को मिली न्यायिक विवेकाधिकार शक्ति का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाना चाहिए; इसके लिए आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक के न्याय से भागने की संभावना और अन्य कारकों पर अच्छी तरह विचार करना ज़रूरी है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यह प्रकरण अग्रिम ज़मानत देने के लिए उपयुक्त है। अग्रिम ज़मानत देने से कुछ हद तक अपराध की विवेचना प्रक्रिया में दखल पड़ता है, इसलिए न्यायालय को ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अग्रिम ज़मानत देना कोई नियम नहीं है और यह तभी दी जानी चाहिए जब न्यायालय को यकीन हो जाए कि इस असाधारण उपाय को अपनाने के लिए खास परिस्थितियां मौजूद हैं।"

11. यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का ज़िक्र करना सही होगा, जिसका शीर्षक है किशोर विश्वासराव पाटिल बनाम दीपक यशवंत पाटिल और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528; इसके संबंधित प्रस्तर संख्या 14 और 15 इस प्रकार हैं:

"14.....



74. आम तौर पर, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है जिसका मकसद कई उद्देश्यों को पूरा करना होता है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें आरोपी ऐसी जानकारी दे सकता है जिससे अहम तथ्यों और ज़रूरी जानकारी का पता चल सके। अग्रिम ज़मानत देने से विवेचना में बाधा आ सकती है। अग्रिम ज़मानत का मकसद व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार और विवेचना अभिकरण के उस अधिकार के बीच संतुलन बनाना है, जिसके तहत वह आरोपी से अब तक इकट्ठा की गई सामग्री के बारे में पूछताछ कर सके और और जानकारी इकट्ठा कर सके जिससे ज़रूरी जानकारी मिल सके.....

6.....

75. यह देखते हुए कि गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसका मकसद कई उद्देश्यों को पूरा करना है, अद्रि धरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [अद्रि धरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2005) 4 एससीसी 303: 2005 एससीसी (क्रि) 933] प्रकरण में यह कहा गया था: (एससीसी पृष्ठ 313, प्रस्तर 19)

"19. आम तौर पर, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है जिसका मकसद कई उद्देश्यों को पूरा करना होता है। आरोपी से अपराध के मकसद, तैयारी, अपराध करने और उसके बाद की घटनाओं, और अपराध में शामिल अन्य लोगों (यदि कोई हों) के संबंध के बारे में विस्तार से पूछताछ करनी पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें आरोपी ऐसी जानकारी दे सकता है जिससे अहम तथ्यों का पता चल सके। विवेचना को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने और साक्षियों तथा अपराध के पीड़ित से जुड़े लोगों की सुरक्षा करने, आरोपी के गायब होने से रोकने और इलाके में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी आज़ादी पर रोक लगाना ज़रूरी हो सकता है। इन या अन्य कारणों से, गिरफ्तारी विवेचना प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा बन सकती है। संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन पर विचार करते समय प्रस्तावित गिरफ्तारी की विधिक वैधता पर बात नहीं की जा सकती।

विवेचना करने वाले की भूमिका अच्छी तरह से तय है और विवेचना की प्रक्रिया में न्यायालय के दखल का दायरा सीमित है। न्यायालय आम तौर पर किसी अपराध की विवेचना या संज्ञेय अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी में दखल नहीं देगा। अगर संहिता की धारा 438 के तहत आवेदन पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी रोकने का कोई अंतरिम आदेश दिया जाता है, तो यह विवेचना में दखल माना जाएगा, जो किसी भी हाल में संहिता की धारा 438 के तहत नहीं किया जा सकता।"

76. **सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2011) 1 एससीसी 694: (2011) 1 एससीसी (क्रि) 514]** प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों और पैमानों को तय किया। यह कहा गया कि अग्रिम आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा आरोपी की सटीक भूमिका को ठीक से समझा जाना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। यह भी कहा गया कि न्यायालय को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे नुकसान पहुँचाने या अपमानित करने के मकसद से लगाए गए हैं।

77. **सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे [सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694: (2011) 1 एससीसी (क्रि) 514]** और अन्य फैसलों का जिक्र करने और यह देखते हुए कि अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, **जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य [जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य, (2012) 4 एससीसी 379: (2012) 2 एससीसी (क्रि) 468]** प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा: (एससीसी पृष्ठ 386, प्रस्तर 19)

"19. गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत देने के लिए ज़रूरी शर्तों को पूरा करना होता है और ऐसी राहत देते समय न्यायालय को इसके कारण भी दर्ज करने होते हैं। अग्रिम जमानत केवल खास हालात में ही दी जा सकती है, जब न्यायालय को पहली नज़र में यह लगे कि



आवेदक को अपराध में झूठा फँसाया गया है और वह अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। (देखें डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरण [डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरण, (2007) 4 एससीसी 434 : (2007) 2 एससीसी (क्रि) 345], महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद। साजिद हुसैन मो. एस. हुसैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद। साजिद हुसैन मो. एस. हुसैन, (2008) 1 एससीसी 213: (2008) 1 एससीसी (क्रि) 176] और भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल [भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल, (2008) 13 एससीसी 305: (2009) 1 एससीसी (क्रि) 111])”

आर्थिक अपराध

78. दंप्रसं की धारा 438 के तहत मिलने वाली शक्ति एक असाधारण उपाय है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर और कम ही किया जाना चाहिए; खासकर आर्थिक अपराधों के मामलों में। आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे समाज के आर्थिक ढांचे पर असर डालते हैं। प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन [प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन, (1998) 2 एससीसी 105: 1998 एससीसी (क्रि) 510] प्रकरण में यह कहा गया था कि आर्थिक अपराधों में आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं होता है।”

15. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा:-

“92.4. अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदनकर्ता की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत दी जाए या नहीं, यह न्यायालय



के विवेक पर निर्भर करता है; साथ ही, अगर ज़मानत दी जाती है,
तो किस तरह की विशेष शर्तें लगाई जाएं (या न लगाई जाएं), यह
भी प्रकरण के तथ्यों और न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।”

12. प्राथमिकी और विवेचना में बताई गई बातों के अनुसार, आवेदनकर्ता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवेचना अभी शुरुआती चरण में है, और सच्चाई का पता लगाने के लिए आवेदनकर्ता से हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है। आवेदनकर्ता के अधिवक्ता यह साबित करने में नाकाम रहे हैं कि उनके खिलाफ दर्ज प्रकरण झूठा है। इस चरण में, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि आवेदनकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण नहीं बनता है। अभिलेख पर आए साक्ष्य और शुरुआती विवेचना से आरोपों के लिए एक उचित आधार बनता हुआ दिखता है।

13. इस न्यायालय की राय में, नियमित ज़मानत और अग्रिम ज़मानत देने के पैमाने अलग-अलग हैं और यह ज़रूरी नहीं है कि जो आधार किसी आरोपी को नियमित ज़मानत पर रिहा करने के लिए काफी हों, वे उसे अग्रिम ज़मानत पर रिहा करने के लिए भी काफी हों। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने **गुरबख्श सिंह सिब्बिया और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 565** प्रकरण में भी यह कहा था कि अग्रिम ज़मानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए, चूंकि यह एक असाधारण शक्ति है, इसलिए इसका इस्तेमाल सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता है।

14. इसलिए, ऊपर बताए गए प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक अग्रिम ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

15. इसी के अनुसार, यह अग्रिम ज़मानत आवेदन **खारिज किया जाता है।**

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

21 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय